the state Government had submitted a proposal to declare two National Highways in Orissa. The first one is Berhampur-Raipur *via* Bhawanipatna which is a very important road and which passes through three important states, that is, Orissa, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. The second one is Banagan-Kharial *via* Bolangir and Titlagarh. Emphasis was laid on this in the Transport Development council meeting held on the 17th October 1985 for taking up this road due to the coming up of the Defence project at Sainthala in the district of Bolangir. I would like to know from the hon. Minister what happend to these two new roads?

SHRI RAJESH PILOT: Sir, it is a fact that the National Transport Policy Committee recommended these two roads, Berhampur to Raipur and Balasore to Gorakhpur. But as I mentioned, Sir, due to acute shortage of resources in this sector we have not been able to really sanction these two projects. But in this new plan which we are considering, some important roads are there which can be taken care of in the next plan.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: I would like to know from the hon. Minister whether there is a plan to construct a road Raxaul to Orissa *via* Bihar.

SHRI RAJESH PILOT: It is difficult for me now to give the location of this and what is the progress.

MR. CHAIRMAN: He will look into it (*interruptions*) Next question.

*429. [*The questioners (Shri T. R. Balu and Shri V. Gopalsamy) were absent. For answer,* vide *col.* 38 *infra*].

Blindness among children due to lack of non-essential drugs

*430. SHRI NARESH C. PUGLIA: †
SHRIMATI RATAN KUMARI:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report in the 'Indian Express' of 28th September, 1986 to the effect that about 30,000 children who go blind every year in the country, are often victims of non-essential drugs;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF HEALTH IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) Yes, Sir. We have seen the press report. While, Government are not aware of any recorded evidence to support the claim in the report, the Royal Commonwealth Society for the Blind reported in 1970 that 42,000 children in 1—5 years age group in India develop blindness every year due to malnutrition.

(b) and (c) A National Blindness Survey is in progress which will also cover the extent of occurrence of blindness in children and the causes for it.

Under National Programme for Control of Blindness, eye care services are being provided in stages at primary, secondary and tertiary levels coupled with Health Education measures. Vitamin 'A' prophylaxis programme has been undertaken through network of MCH services to cover children below 6 years.

श्री नरेश सी० पुगलिया : सभापति जी, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इस चीज को कबूल किया है कि 1978 में रायल कामनवैल्थ सोसाइटी फार दि ब्लाइंड ने जो रिपोर्ट दी है उसमें पांच वर्ष से कम

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Naresh C. Puglia.

आयु के बच्चे, 42 हजार बच्चे हर वर्ष कुपोषण के कारण दृष्टिहीन हो जाते हैं। हाल ही में डा० राजेन्द्र प्रसाद और डा० मदन ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारे देश में एक करोड़ दस लाख नेत्रहीन व्यक्ति है जिन्हें हम समय पर चिकित्सा नहीं दे सके। इसका मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रीय लैवल पर इस डिपार्टमेंट ने 125,150 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए विनती की थी लेकिन उसकी तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 31 करोड़ रू. की प्लांनिग कमीशन ने मंजरी दी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए खासकर 8 साल की उम्र से कम जो बच्चे हैं, उनमें से आठ परसेंट की आंखें खराब हो गयी है और 3 परसेंट को समय पर चिकित्सा नहीं दे पाये हैं, इस कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए सातवीं योजना में इस राशि की वृद्धि करने में इस डिपार्टमेंट का क्या विचार है ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : पहले तो मुझे यह बताना है कि यह जो रायल कामनवेल्थ सोसाइटी फार दि ब्लाइंड यू के में है उसकी तरफ से या उसके एक एक्सपर्ट ने कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं कियां, कहीं-कहीं पाकेटस में वे गये और वहां से रिपोर्ट लेकर एक यह आंकड़ा दिया है। मैं यह नहीं कहता कि यह आंकड़ा सही है या गलत है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से जो सर्वेक्षण हो रहा है और जिसका नतीजा सन् 87 में आना है उसमें हम को और ज्यादा विश्वसनीय आंकड़े हो सकता है, मिलें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह जो अंधत्व है यह बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमने जो - जो उपाय किये है या कर रहे हैं उनमें एक तो विटामिन 'ए' सोल्यूशन एंड केपसूल्स, सल्फा एन्टी वायटिक्स आई ड्रोप्स आइन्मेंटस यूज्ड लोकली, एन्टोफीन, यह तो वहाँ के लिए हैं जो डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। यह बहुत बड़ा देश ब्यापी कार्यक्रम लिया गया है। यह सही है कि जितना पैसा इसके लिए जुटाना चाहिए उतना पैसा हम जुटा नहीं सके हैं। लेकिन होते-होते हम पैसा और ज्यादा जुटाने की कोशिश करेंगे और वह किया जाएगा। एक बात यह भी है कि इस प्रश्न में थोड़ी-सी गलतफहमी होने की संभान्ना है। इसमें लिखा गया है--

"30,000 children who go blind every year in the country are often victims of non-essential drugs." They are not victims of non-essential drugs. There is no such thing as non-essential drugs. Non-availability of essential drugs may lead to it. It is not because of non-essential drugs. So, we are trying to step up the availability of essential drugs. We are doing that to a large extent. This is a continuous process. It cannot be done overnight.

श्री नरेश सी० पुगलिया : सभापति जी, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के (ख) भाग में कहा है कि एक राष्ट्रीय दृष्टिहीनता सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसमें बच्चों में दृष्टिहीनता की व्यापकता की मात्रा का और इसके कारणों का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सन् 1983 से अब तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन मंत्री महोदय कहते है कि सन् 1987 में इस प्रकार के सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ जाएगी, तो इस समिति का गठन कब से किया गया है और सर्वेक्षण का काम कहां तक हुआ है, किन-किन राज्यों के फीगर्स आ चुकी हैं ? (बी) में मैं यह पूछना चाहता हूं कि सन् 1986-87 में किन-किन प्रान्तों को कितनी राशि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई है ?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, it is very difficult to give State-wise figures. I can send them to the hon. Member. I only said that his survey is in progress now. The results will be available in 1987. The date on which it was constituted is not readily available with me. I can give it to him.

श्री अश्विनी कुमार : सभापति जी, देश में जो अन्धापन है उसके बारे में सरकार ने कहा है कि हम सवक्षण कर रहे हैं और

इसकी रिपोर्ट आगे रखेंगे । यह रिपोर्ट आने के बाद कुछ चर्चा भी होगी । लेकिन आंखों की बहुत सी बीमारियां होती हैं केटेरेक्ट वगैरह, उसके लिये आपरेशन होते हैं । ये आपरेशन वालेन्टरी आर्गेनाईजेशन करते हैं । उनके माध्यम से कई बार मिस्हैप हुई है । इन मिस्हैप के बारे में सरकार के पास रिपोर्ट भी आई होगी । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कितनी ऐसी मिस्हैप्स हुई हैं और उनको रोकने के लिये सरकार कौन से कदम उठाने की सोच रही है जिससे कि जो वालेन्टरी आर्गेनाइजेशन अच्छा काम करने वाली हैं उनका उत्साह खत्म न हो, परन्तु जो गलत काम करने वाले है उनको रोकने के लिये कोई ठीक व्यवस्था की जाये ? मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, इस पर काफी लम्बी चर्चा सेन्ट्रल कांसिल आफ हेल्थ में हुई है । हमने गंभीरता से इस बात को लिया है । सेन्ट्रल कौंसिल आफ हैल्थ की एक कमेटी गठित हो रही है जो इस मामले की पूरी तरह से तफसील में जायेगी और हमें बतायेगी कि इसमें हमें क्या-क्या उपाय सोचने चाहिये । वैसे यह काम राज्य सरकारों की देखरेख में, उनके तत्वावधान में होता है । उनसे बात करके यह कमेटी हमें बतायेगी कि इसका फूल-प्रूव क्या हो, जो दुर्घटना हो रही है उनको कम से कम करने के लिये बल्कि पूरी तरह से हटा देने के लिये क्या-क्या करना है, यह सब हमें बतायेगी । इसमें एक उपाय नहीं है, यह कम्बीनेशन से होगा । कहीं-कहीं पर जो आपरेशन होते हैं वे अच्छे होते हैं, लेकिन उन मामलों की आफटर केयर ठीक नहीं होती है जिससे आदमी अन्धा हो जाता है । इस तरह से हमें कई उपाय सोचने पड़ेंगे । उस कमेटी से हमने कहा है कि इस मामले में तफसील में हमें रिपोर्ट दे ।

ठाकुर जगतपाल सिंह : माननीय सभापति जी, क्या माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर अन्धेपन को रोकने के लिये कोई कार्यक्रम बनायेंगे ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, यह तो हमने जवाब में पढ़ लिया है ।

कुमारी सरोज खापर्डे : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दे दिया है । लेकिन फिर भी उनको मैं बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्तर पर अन्धेपन के कंट्रोल के लिये जो योजना बनाई गई है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि 1.4 परसेंट अन्धापन जो था वह 1975 में था : और वह 1.4 से 0.3 प्रतिशत तक 2000 ए०डी० तक ला पायेंगे, उसको कंट्रोल कर पायेंगे, रिड्यूस कर पायेंगे । इस प्रोग्राम में इसको मेन इम्फेसिस दे रहे हैं

"to perform timely cataract operations by camps district control units, etc. Cataract in the eye is responsible for more than 50 per cent of the blindness cases."

राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है उसके द्वारा, उसके माध्यम से यह कार्यक्रम हम लोगों को देना चाहते हैं, इम्लीमेंट करना चाहते हैं ।

श्री शरद यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अंधे बच्चे जो हैं वे हिन्दुस्तान में पैदा होते हैं

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अंधे बच्चे पैदा होते हैं ।

श्री शरद यादव : हां, दुनिया में सबसे ज्यादा अंधे बच्चे हिन्दुस्तान में पैदा होते हैं, बार्न बलाइंड । दूसरा मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि अभी जसा कि एक माननीय सदस्य ने पूछा कि वालेन्टरी आर्गनाइजेशन जो आपरेशन कर रहे हैं तो यहां से मुश्किल से सौ किलोमीटर दूर हापुड़ में 50 लोग अभी भी अंधे हैं । आपने इसके लिये कमेटी बनाई है, वह तो ठीक बात है । लेकिन वह कब तक रपट देगी ? क्या जो 50 लोग अंधे हो गये हैं तो क्या इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कुछ किया है या आपने उनको कार्यवाही करने के लिये कहा है ?

कुमारी सरोज खापर्डे : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसके उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां से सौ किलोमीटर की दूरी का जो उन्होंने गांव बताया है और उसमें जो घटना हुई है उसके लिये हमने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है और ऐसी घटनायें बार बार न हों इसका प्रीकाशन लेने के लिये कहा है। आपने जो . . .

श्री शरद यादव : कार्यवाही . . .

कुमारी सरोज खापर्डे : कार्यवाही शुरू हो गई है। आपने जो पहले प्रश्न किया है कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे अंधे पैदा होते हैं तो आपके इस विधान से मैं सहमत नहीं हूं। हिन्दुस्तान में अधिक बच्चे जरूर पैदा होते हैं लेकिन अंधे अधिक पैदा होते हैं इससे मैं सहमत नहीं हूं।

डा० बापू कालदाते : सभापति महोदय, मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया उसको सुनाकर आश्चर्य हुआ। एक तरफ आप हम को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अंधत्व पर सर्वेक्षण जारी है और अभी मंत्री महोदया ने कहा कि इस देश में 1.4 से घटाकर 0.3 प्रतिशत की हद तक इस अंधत्व के प्रतिशत में कमी हुई है। जबकि आपके पास सर्वेक्षण ही नहीं है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि यह 1.4 से 0.3 प्रतिशत की हद तक आया है ?

दूसरी बात यह है कि आप यह कहते हैं कि अंधत्व का कारण विटामिन डेफिसैंसी है और आप यह कह रहे हैं कि हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि यह विटामिन लोगों को दिये जायें, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि औसतन, एवरेज कितने बच्चों को आप विटामिन 'ए' दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय मेरे इन दो सवालों का जवाब दें ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, यह जो कार्यक्रम है यह अलग नहीं है। हमारे आई०सी०डी०एस० और एम० ०एच० कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। उनका जो कवरेज होगा, उसी के बराबर इसका कवरेज भी होगा क्योंकि हमने इसको एक अलग कार्यक्रम नहीं बनाया है। हमारा जो बच्चों का व्यापक कार्यक्रम है इसका एक अंग बनाया है और वही बनना चाहिये। इसलिये कि अलग बनाना चाहेंगे तो वह काम चलेगा नहीं, दोनों में काफी टकराव भी हो सकता है। इसलिये हमने इसको व्यापक कार्यक्रम का एक भाग बनाया है। अब दूसरी जो बात यह है सर्वेक्षण अब जो किया जा रहा है वह ऐसा सर्वेक्षण है इन-डेप्थ। अब रायल कमीशन वालों ने, एक आदमी ने आकर सर्वेक्षण किया तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि उसने सर्वेक्षण नहीं किया। लेकिन हम यह बात कह सकते हैं कि जो देशव्यापी सर्वेक्षण इस पर कर रहे हैं इससे पहले कभी ऐसा सर्वेक्षण नहीं हुआ है। समय-समय पर जो भी सर्वेक्षण होते गये हैं उनसे हमें कुछ न कुछ आंकड़े मिलते हैं और अंदाजन ही सही हमको यह बताना पड़ा कि इस आंकड़े से इस आंकड़े तक घटे हैं, इसके इंसीडेंटस घटे हैं। लेकिन यह एकदम ऐसी बात नहीं है जैसे कि हम सोना तोल रहे हों, इसमें थोड़ा बहुत अन्तर भी हो सकता है।

श्री राम चन्द्र विकल : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो सर्वेक्षण आप करा रहे हैं वह राज्य सरकारों के माध्यम से करा रहे हैं या सीधे आपकी मशीनरी द्वारा हो रहा है और यह 1987 तक जो रिपोर्ट आयेगी अब तक कोई इसके बारे में जानकारी है कि इसमें क्या प्रगति हुई है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कब से यह कमेटी शुरू हुई है ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : यह जारी है। यह हमारा सवक्षण है, राज्य सरकारों का नहीं है। जाहिर है कि जब हम सर्वेक्षण करने जाते हैं तो राज्य सरकारों से मदद भी लेंगे उसके बगैर एकदम जा कर हम नहीं करते हैं। उनसे जितनी मदद हो सकती है हम लेते हैं और वह देते भी हैं। 1987 में वह रिपोर्ट आने वाली है इसलिये अब थोड़ा सा इंतजार कीजिये।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, the magnitude of the problem can be gauged by the mere fact that 30,000 children get blind only on account of the non-availability of essential drugs. What about the substantive diseases? What is the number of casualties with respect to substantive diseases like cataract and others? Sir, I feel that this problem can be tackled only on a national level if only this thing is brought to the district level. Will the Minister consider a suggestion from me that he shall right from now on even in cities other than Delhi—of course the hospitals have a section where eye-treatment is done—but will the hon. Minister consider that in view of the magnitude of the problem that he will evolve a scheme that in every district of the country an eye hospital will be established and 50 per cent of the expenditure will be borne by the Centre so that the State Governments set up these as seeparate hospitals to cater to the needs of the people in the district?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, the answer clearly says that under the national programme for control of blindness eye care service centres are being provided in States at Primary, i.e., the primary health centre, at Secondary, i.e., the district, and also at the Tertiary level. Tertiary level naturally means the medical colleges and bigger hospitals. So, at all the three levels it is being simultaneously provided. Now, the provision as it is being made now and the coverage as it is being achieved now is not adequate and what needs to be done is more coverage, more money, more funds and not going really anywhere down below that primary health centre. It is well known that we are actually having this programme at all the three levels.

Immunisation scheme for triabals in Bihar

*431. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that population of tribals in Santhal Paragana and Chhotta Nagpur in Bihar is decreasing day by day with increase in death rate, if so the reasons thereof;

(b) whether Government propose to start any mass immunisation programme in these two places of Bihar;

(c) if so, what are the details of the programme and by when it will be started; and

(d) if the answer to part (b) be in nagative, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF HEALTH IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) According to the last three Census, there is no decline in the total population of scheduled tribes in the areas of Chhotta Nagpur and Santhal Paragana.

(b) and (c) The Expanded Programme of Immunization was started in 1978 with the objective of providing immunization against major vaccine preventable diseases among pregnant women and infants. From 1985-86, the Universal Immunization Programme has been started to provide a total coverage for pregnant women and infants by 1990. Chhotta Nagpur and Santhal Paragana are having Expanded Programme of Immunization and other health related activities. Universal Immunization Programme will be extended to Dhanbad and Singhbhum Districts in Chhotta Nagpur in 1987.

(d) Does not arise.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : सभापति महोदय, मंत्री महोदया ने सेंसस का हवाला देते हुए कहा है कि मृत्यु की संख्या में कमी नहीं हो रही है। क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि पिछले तीन सेंससों में डेथ रेट और बर्थ रेट क्या क्या रहे हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, जब यह कहा जाता है कि उनकी आबादी कम हो रही है उसी के जवाब में हमने कहा कि उनकी जो कुल आबादी है वह कम नहीं हो रही है लेकिन उनका प्रतिशत घट सकता है। यह इसलिए कि जब नान-ट्राइबल लोग वहां किसी भी कारण